RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 17 MARCH TO 23 MARCH 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 30 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

जीएसटी क्षतिपूर्ति 2021-22 में पड़ सकती है 3 लाख करोड़ रुपये कम, राज्यों को लेना पड़ सकता है कर Page 3

OPEC देशों को झटका देने के तैयारी में भारत Page 4

बेंटले ने उतारा बेंटाइगा एसयूवी का नया संस्करण, कीमत 4.10 करोड़ रुपये Page 7

editoria!

क्वाड शिखर बैठक

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत- इन चारों देशों के सत्ताशीर्ष की शुक्रवार को हुई वर्चुअल बैठक को दुनिया के राजनयिक हलकों में एक गंभीर परिघटना के रूप में दर्ज किया गया है। क्वाड नाम से चर्चित इस गठबंधन को चीन विरोधी व्यापक गोलबंदी की धुरी माना जा रहा है। एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच के रूप में यह 2007 से कायम है लेकिन इसकी शिखर बैठक पहली बार ही आयोजित हुई है और यही क्वाड की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा है। यह अकारण नहीं है कि चीन ने इस बैठक को लेकर खुलकर अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बैठक से ठीक पहले इस विषय में साफ-साफ कहा कि विभिन्न देशों के बीच विचार-विमर्श और सहयोग की प्रक्रिया चलती रहती है लेकिन इसका मकसद आपसी विश्वास और समझदारी बढ़ाने का होना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने या उसके हितों को नुकसान पहुंचाने का नहीं। जाहिर है, चीन को यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में उसके आक्रामक रुख से ये सभी देश किसी न किसी स्तर पर आहत या आशंकित महसूस करते रहे हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि चीन के बयान की यहां अनदेखी नहीं की गई। क्वाड शिखर बैठक में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि उसको किसी खास देश के खिलाफ न माना जाए। बातचीत का अजेंडा कोविड वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और नई तकनीकों से संभावित बदलाव जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित रखा गया। एशिया-प्रशांत क्षेत्र का जिक्र आया भी तो बहुत खुले ढंग से। साफ है कि क्वाड देशों ने इस शिखर बैठक के जरिए अभी सिर्फ एक संभावना की ओर संकेत किया है। इन चारों देशों की अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं और उनके आपसी सहयोग की एक सीमा है। इसी महीने की 18 तारीख को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन अलास्का में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग के प्रोफाइल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद दोनों देशों के आला सरकारी प्रतिनिधियों की यह पहली सीधी मुलाकात है। पिछले तीन वर्षों से हम चीन और अमेरिका में हर मोर्चे पर टकराव ही देखते आ रहे हैं। दोनों देशों के आपसी रिश्तों के अगले दौर का खाका काफी कुछ इस बैठक से ही स्पष्ट होगा। दूसरी तरफ इसी तारीख, 18 मार्च को मॉस्को में एक बैठक रूस ने रखी है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान के प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस देश का भविष्य तय करेंगे। पिछले पंद्रह सालों में भारत ने अफगानिस्तान में अरबों रुपये लगाए हैं और कई बेशकीमती शहादतें दी हैं, फिर भी इस बैठक के लिए उसको पूछा नहीं गया। इन दोनों बैठकों का नतीजा जो भी निकले, इनके होने भर से एक बात साफ है कि हमारे राष्ट्रीय हित किसी और देश के साथ नत्थी होकर नहीं सधने वाले हैं।

तीन तेल भंडारों को भरकर सरकार ने बचाएं 5,000 करोड़ रुपए

नए बनाने में अड़चन

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में रणनीतिक तेल भंडारों की बढ़ती जरूरत के बावजूद इनके निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं। मौजूदा तीनों भंडारों को सरकार ने पिछले वर्ष बेहद सस्ता हुए कच्चा तेल से भरकर 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की है। इसके बावजूद देश में दो नए रणनीतिक तेल भंडार बनाने की राह आसान नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार ने जून, 2018 में ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में 65 लाख टन की संयुक्त क्षमता के दो रणनीतिक भंडार बनाने का फैसला किया था। यह भूमि अधिग्रहण में विलंब की वजह से लंबित चल रहा है।

केंद्र सरकार की इन दोनों परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकारों से बात हो रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी भी बताने की स्थिति में नहीं हैं कि यह काम कब तक पूरा होगा। हाल ही में संसदीय समिति ने भी एक रिपोर्ट में इस परियोजना में होने वाली देरी को लेकर अपनी चिंता जताई है। अभी देश में विशाखापत्तनम, मेंगलुरु और पादुर में क्रमश 13.3 लाख टन, 15 लाख टन और 25 लाख टन क्षमता के कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार हैं। इन तीनों भंडारों में देश की 9.5 दिनों की खपत के बराबर क्रूड जमा किया जा सकता है। हाल के दिनों में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड काफी सस्ता था तब भारत सरकार ने इन तीनों भंडारों को भर लिया है। चंडीखोल और पादुर में जो नए भंडार बनाने की तैयारी है उससे देश की क्षमता के 12 दिनों के बराबर तेल रखा जा सकेगा। इसके अलावा भारत अमेरिका में भी कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार खरीदने पर काम कर रहा है। सरकार की योजना है कि आने वाले दिनों में भारत के पास आपातकालीन हालात में कम से कम 30 दिनों का तेल भंडार हो। पिछले वर्ष सरकार ने तीनों भंडारों को भरने के लिए 3,184 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत में पहले सिर्फ 690 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था लेकिन जब अंतराष्ट्रीय कीमतों में कमी आई तो अतिरिक्त आवंटन किया गया। बताया जाता है कि जब अप्रैल-मई में जब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति काफी कम हो गई थी तब सरकारी कंपनियों की रिफाइनरियों ने आयातित तेल को रणनीतिक भंडारों में रखना शुरू कर दिया था। इससे सरकार को 5,069 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

सरकार ने माना कि डीजल-पेट्रोल से होती है तगड़ी कमाई, लेकिन जीएसटी में लाने का प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में पेट्रोलियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में एक जुलाई, 2017 को जब जीएसटी लागू की गई तो पेट्रोलियम उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। केंद्र और राज्य सरकारों के कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन उत्पादों पर लागू करों पर निर्भर करता है। इससे पहले लोकसभा में अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि पेट्रोल-डीजल से सरकार की तगड़ी कमाई होती है। सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "फिलहाल, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई

प्रस्ताव नहीं है।' उन्होंने कहा कि कानून के तहत जीएसटी परिषद ही अनुशंसा कर सकती है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर किस तिथि से जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया, "अब तक जीएसटी परिषद ने इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई अनुशंसा नहीं की है।" सीतारमण के अनुसार, जीएसटी परिषद जब संबंधित कारकों को देखते हुए जब उचित समझेगी तो इन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। उधर, लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर कुछ कर राज्य लगाते हैं और कुछ केंद्र लगाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार भी इन पर कर कम करें और हम (केंद्र) भी ऐसा करें, दोनों इस बारे में विचार करें। अनुराग ठाकुर ने कहा, "जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का सवाल है, इस विषय को जीएसटी की शुरूआत के समय खुला रखा गया था। इसमें कहा गया था कि जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र मिलकर तय कर सकते हैं कि इसे कब इसके दायरे में लाना है।"

वित्त वर्ष में अब तक 2.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर रिफंड

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2.09 करोड़ लोगों को 2.04 लाख करोड़ रुपये का रिफंड किया है। विभाग के मुताबिक इसमें से 2.06 करोड़ आयकरदाताओं को 73,607 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड किया है जबकि 2.21 लाख मामलों में 1.31 लाख करोड़ रुपये का कार्पोरेट कर रिफंड जारी किया गया है। विभाग ने ट्वीट कर कहा है, "सीबीडीटी ने पहली अप्रैल 2020 से लेकर 15 मार्च 2021 तक 2.09 करोड़ करदाताओं को 2,04,805 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है।"

डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे कमजोर खुला

नई दिल्ली। एजेंसी

विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज बुधवार यानी 17 मार्च 2021 को कमजोरी के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की तेजी के साथ 72.58 रुपये के स्तर पर खुला। वहीं, मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 72.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। डॉलर में कारोबार काफी समझदारी से करने की जरूरत होती है, नहीं तो निवेश पर असर पड़ सकता है।

जानिए पिछले 5 दिनों के रुपये का क्लोजिंग स्तर -मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की कमजोरी के साथ 72.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 31 पैसे की मजबूती के साथ 72.46 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ 72.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे की मजबूती के साथ 72.92 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। -सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे की कमजोरी के साथ 73.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था।

आजादी के समय रुपये का स्तर एक जमाना था जब अपना रुपया डॉलर को जबरदस्त टक्कर दिया करता था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो डॉलर और रुपये का दाम बराबर का था। मतलब एक डॉलर बराबर एक रुपया था। तब देश पर कोई कर्ज भी नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपये की साख भी लगातार कम होने लगी। 1975 तक आते-आते तो एक डॉलर की कीमत 8 रुपये हो गई और 1985 में डॉलर का भाव हो गया 12 रुपये। 1991 में नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत ने उदारीकरण की राह पकड़ी और रुपया भी धड़ाम गिरने लगा। डिमांड सप्लाई तय करता है भाव करेंसी एक्सपर्ट के अनुसार रुपये की कीमत पूरी तरह इसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी इस पर असर पड़ता है। हर देश के पास उस विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, जिसमें वो लेन-देन करता है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा की चाल तय होती है। अमरीकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है और ज्यादातर देश इंपोर्ट का बिल डॉलर में ही चुकाते हैं।

पहली वजह है तेल के बढ़ते दाम रुपये के लगातार कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के बढ़ते दाम हैं। भारत कच्चे तेल के बड़े इंपोर्टर्स में एक है। भारत ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसका बिल भी उसे डॉलर में चुकाना पड़ता है। दूसरी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजारों में अक्सर जमकर बिकवाली करते हैं। जब ऐसा होता है तो रुपये पर दबाव बनता है और यह डॉलर के मुकाबले टूट जाता है।

राजस्थान को खनिज तेल से दो साल में 7203 करोड़ रुपये की आय

जयपुर। एजेंसी

राजस्थान को पिछले दो साल में खनिज तेल से 7203 करोड़ रुपये से अधिक की आय हुई है। राज्य के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत दो वर्ष में खनिज तेल से राज्य को 7203.32 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में फरवरी तक 1653.85 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है।

भाया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खनिज से प्राप्त राजस्व में पेट्रोलियम, गैस संबंधी राजस्व को केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि लेड तथा जिंक को 1956 की उद्योग नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था। वर्ष 1993 में जिंक लेड सहित 13 खनिजों को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। उन्होंने बताया कि उत्पादन के आधार पर राजस्व आय कम या अधिक होती रहती है।

इससे पहले विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में भाया ने बताया कि राज्य सरकार को प्रधान व अप्रधान खनिजों से खनिज राजस्व के रूप में आय प्राप्त होती है। विगत दो साल में प्रधान खनिज से वित्त वर्ष 2018-19 में 3221.98 करोड़ व वर्ष 2019-2020 में 2595.53 करोड़ तथा गैर-प्रमुख खनिज से वर्ष 2018-19 में 1953.41 करोड व वर्ष 2019-20 में 1837.69 करोड़ रुपये आय हुई। इस तरह से वित्त वर्ष 2018-19 में कुल खनिज आय 5175.39 करोड़ रुपये व वर्ष 2019-20 में 4433.22 करोड़ रही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एल्युमिनियम (बॉक्साईट) के भण्डार बारां व उदयपुर जिले में तथा लेड-जिंक के भण्डार उदयपुर, राजसमन्द, भीलवाडा, अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में है।

खुदरा क्षेत्र में बिक्री फरवरी में कोविड-पूर्व के 93 प्रतिशत स्तर पर पहुंची

नयी दिल्ली। एजेंसी

खुदरा क्षेत्र का कारोबार लगभग पटरी पर आ गया है। यह क्षेत्र बिक्री के मामले में कोविड- पूर्व स्तर के 93 प्रतिशत तक पहुंच गया है। रिटेलर्स एसोसिएशन की ऑफ इंडिया (आरएआई) की रिपोर्ट के अनुसार टिकाऊ उपभोक्ता और तुरंत सेवा देने वाले रेस्तरां (क्यूएसआर) क्षेत्र में इस साल फरवरी में क्रमशः 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इसमें कहा गया है कि खुदरा बिक्री में जो गिरावट थी, वह कम हुई है। ज्यादातर क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले हैं। जूता-चप्पल, रूप-सज्जा और स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद, खेल के सामान, खाद्य और किराना क्षेत्रों में मासिक आधार पर लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ''रिटेलर्स एसोसिएशन का खुदरा व्यापार सर्वे का 13वां संस्करण यह संकेत देता है कि फरवरी में सालाना आधार पर बिक्री में 7 प्रतिशत की कमी आयी है। जबकि तिमाही आधार पर कमी 18 प्रतिशत है।'' इसमें कहा गया है कि यह सुधार देश में हर क्षेत्र में क्षेत्रों में देखा जा रहा है। पूर्वी भारत में फरवरी महीने में 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। रिपोर्ट के अनुसार, ''दक्षिण और उत्तर भारत में भी बेहतर सुधार देखने को मिला है। इन क्षेत्रों में बिक्री लगभग कोविड पूर्व स्तर पर आ गयी है और बिक्री में सालाना आधार पर क्रमशः 6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की गिरावट आयी। हालांकि पश्चिमी भारत में प्रगति कुछ धीमी है। वहां बिक्री में सालाना आधार पर फरवरी में 16 प्रतिशत की कमी आयी है।'' आरएआई के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को कारोबार 2021 के पहले छह महीने में माहमारी-पूर्व स्तर पर आने की उम्मीद है।

2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य : प्रधान

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। प्रधान ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू किया गया था।

लेकिन उसके बाद संप्रग सरकार के कार्यकाल में इस नीति पर खास ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में यह सरकार सत्ता में आयी तो उस समय पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का प्रतिशत सिर्फ 0.67 प्रतिशत था जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपये से भी कम था। प्रधान ने कहा कि 2020-21 में यह प्रतिशत बढ़कर 8.5 हो गया जिसका मूल्य 18,000 करोड़ रूपए है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का है। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ गन्ना से तैयार होने वाले एथनॉल पर ही जोर था लेकिन अब इसमें चावल और मक्का को भी शामिल किया जा रहा है क्योंकि ये दोनों अनाज उपभोग से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति से किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

संसदीय समिति ने समुद्र में विलीन द्वारका शहर में समुद्री पुरातात्विक अनुसंधान करने का सुझाव दिया

नयी दिल्ली। एजेंसी

संसद की एक समिति ने सरकार को गुजरात में समुद्र में विलीन हुए शहर द्वारका के बारे में जानकारी जुटाने के लिये समुद्री पुरातात्विक अनुसंधान करने का सुझाव दिया है। संसद में पेश 2021-22 के लिये संस्कृति मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है, '' समिति चाहती है कि मंत्रालय गुजरात के विलुप्त (समुद्र में विलीन) शहर द्वारका में व्यापक समुद्री पुरातात्विक अनुसंधान करे।''

समिति ने कहा है कि इसी प्रकार से देश में ऐसे कई पुरातात्विक स्थल हो सकते हैं जो अब तक नहीं खोजे गए हों और जहां आधुनिकतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का प्रयोग पुरातात्विक अनुसंधान और खुदाई के लिये किया जा सकता है। समिति ने कहा है कि ऐसे अभियान से पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों की बड़ी खोज हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने यह भी कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का बजटीय आवंटन 2020-21 में 1246.75 करोड़ रूपये से घटाकर 2021-22 में 1042.63 करोड़ रूपये कर दिया गया। समिति ने कहा कि भारत एक सीमित संसाधनों वाला देश है और सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिये यह जरूरी है कि संसाधनों के आवंटन में प्रतिस्पर्धा के सिरों पर प्राथमिकता दी जाए और उपलब्ध धन को अधिक कुशल एवं उत्पादक तरीके से खर्च किया जाए। समिति ने यह सिफारिश की कि एएसआई को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की संभावना तलाशनी चाहिए।

जीएसटी क्षतिपूर्ति 2021-22 में पड़ सकती है 3 लाख करोड़ रुपये कम, राज्यों को लेना पड़ सकता है कर्ज

मुंबई। एजेंसी

राज्यों को अगले वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति में 3 लाख करोड़ रुपये कम पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर मजबूरन बाजार से ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति मद में 2.7 से 3 लाख करोड़ रुपये की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें से उपकर संग्रह में कमी 1.6 से 2 लाख करोड़ रुपये रह सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति में 1.1 लाख करोड़ रुपये की कमी रही लेकिन 90 प्रतिशत से अधिक राशि अब जारी कर दी गयी है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार जीएसटी संग्रह में कमी से राज्यों को बाजार से कम-से-कम 2.2 लाख करोड़ रुपये और कर्ज लेना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें 2021-22 में बढ़ी हुई कर्ज सीमा का 90 प्रतिशत उपयोग करना होगा। इक्रा के कॉरपोरेट क्षेत्र रेटिंग के समूह प्रमुख जयंत रॉय ने कहा, "केंद्र के 2021-22 के जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमान के आधार पर, हमारा अंदाजा है कि राज्यों द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत अधिक कर्ज या 2.2 लाख करोड़ रुपये के बराबर कर्ज होगा। क्योंकि हमारा अनुमान है कि केंद्र से राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी 1.6 से 2 लाख करोड़ रुपये होगी। इसके आधार पर, 2021-22 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में कमी 2.7 से 3 लाख करोड़ रुपये होगी।" पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की शुद्ध उधारी के लिये सामान्य सीमा 2021-22 में जीएसडीपी का 4 प्रतिशत नियत किया जाए। यह मूल उधारी सीमा 3 प्रतिशत से अधिक है। आयोग ने वित्त वर्ष 2022-25 के दौरान राज्यों के लिये 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज की भी सिफारिश की है। लेकिन यह इस शर्त पर है कि राज्य बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करेंगे।

बैंकों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए RBI उठा रहा और कदम

नियामकीय स्तर पर नहीं होगी चूक

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद को बताया कि रिजर्व बैंक नियामकीय और निगरानी क्षमता मजबूत बनाने के लिए और उपाय कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन उपायों से भविष्य में नियामकीय स्तर पर कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में कहा, "रिजर्व बैंक का नियामकीय और निगरानी तंत्र मजबूत हो यह सुनिश्चित करने के लिए हम रिजर्व बैंक के साथ काम करते रहे हैं। मुझे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आश्वासन दिया कि आंतरिक तौर पर एक संस्थागत प्रणाली को और मजबूत बनाया जा रहा है।" सीतारमण शिरोमणि अकाली दल के सदस्य नरेश गुजराल के सवाल का जवाब दे रही थीं। गुजराल ने जानना चाहा कि हाल में बैंकों में धोखाधड़ी को मामलों को देखते हुए क्या सरकार नियामकीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और कदम उठाने पर विचार कर रही है ताकि बैंकों को बेहतर बनाया जा सके और खाताधारकों की रक्षा की जा सके।

अधिकारियों की बढ़ाई जा रही क्षमता

वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक के नियामकीय और निरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। यह काम खास तरह से तैयार किए गए पाठ्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इससे आगे इस तरह के मामले नहीं होंगे और चीजों में सुधार आएगा।" बैंक गारंटी में कमी के बारे में मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर रिजर्व बैंक मंत्रालय के साथ संपर्क में हैं और इस पर गौर किया जाएगा।

अप्रैल से बदल रहे हैं नियम, घट सकती है इन हैंड सैलरी

एजेंसी

देश में अप्रैल 2021 से 4 नए लेबर कोड (Labour Codes) लागू होने वाले हैं। इन लेबर कोड्स में वेतन/मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता, काम विशेष से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दशाओं (OSH) पर संहिता और सामाजिक व व्यावसायिक सुरक्षा संहिता शामिल हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये चारों संहिताएं अधिसूचित हो चुकी हैं और श्रम मंत्रालय ने चारों संहिताओं को अप्रैल से लागू करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने श्रम कानूनों (Labour Laws) में सुधार के लिए कुल 44 तरह के पुराने श्रम कानूनों को चार वृहद संहिताओं में समाहित किया है। इन संहिताओं को लागू करने से देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों-अधिनियमों का नया दौर शुरू होगा।

नए वेज रूल के तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकते हैं। इसकी वजह से कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि ग्रेच्युटी की रकम बढ़ जाएगी, कर्मचारी और कंपनी दोनों का ही पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन (PF Contribution) बढ़ जाएगा। यानी आपके पास सेविंग्स (Savings) बढ़ेंगी। काम करने के घंटों को लेकर श्रम सुधारों (Labour Reforms) के तहत प्रावधान है कि एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम (Overtime) दिया जाए। ऐसे ही 3 महीने में 125 घंटे से ज्यादा ओवरटाइम पर भी काम नहीं कर सकते।

भारत का निर्यात 1- 14 मार्च के दौरान 17 प्रतिशत बढ़कर 14 अरब डालर पर

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश के निर्यात कारोबार में सुधार के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक से 14 मार्च की अवधि में यह 17.27 प्रतिशत बढ़कर 14.22 अरब डालर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में आयात 27.77 प्रतिशत बढ़कर 22.24 अरब डालर पर पहुंच गया। इससे व्यापार घाटा 8.02 अरब डालर का रहा है। एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले यह वृद्धि दर्ज की गई है। जिन क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है उनमें इंजीनियरिंग, चावल, रत्न और आभूषण उल्लेखनीय रहे हैं। वहीं चमड़ा, तिलहन और सभी तरह के तैयार कपड़ों का निर्यात कम हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य अवधि के दौरान सोना, इलेक्ट्रानिक सामान और कीमती पत्थरों का आयात इस दौरान बढ़ा है। देश का निर्यात कारोबार लगातार तीसरे माह बढ़ते हुआ साल-दर-साल आधार पर फरवरी में 0.67 प्रतिशत बढ़कर 27.93 अरब डालर रहा है। इस दौरान व्यापार घाटा 12.62 अरब डालर पर पहुंच गया।

जहां 50 हजार रुपये का पेट्रोल लगता था वहां 2000 रुपये की बिजली लगेगी: गडकरी

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों (Petrol Diesel Price) के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (ऱ्ग्ह ईंब) ने एक बार फिर इलेक्ट्रिक वाहनों (E Vehicles) के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि तेल के भाव बढ़े हैं जिससे लोग त्रस्त हैं। दूसरी कड़वी सच्चाई यह भी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद भी ऑटोमोबाइल वालों का टर्नओवर कम नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। गडकरी ने मीडिया से कहा, 'मैं पिछले 10-12 सालों से कह रहा हूं कि पेट्रोल-डीजल के बजाय एथनॉल यूज करो, इलेक्ट्रिक कार का यूज करो। आज से दो साल के बाद पेट्रोलियम कार और बाइक की कीमत इलेक्ट्रिक कार और बाइक के बराबर होगी। जहां पहले 50 हजार रुपये का पेट्रोल लगता था वहां 2000 रुपये की बिजली लगेगी। और प्रदूषण भी नहीं होगा।' उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई है।

काम का श्रेय सभी को

अपने मंत्रालय के शानदार काम का श्रेय सभी को देते हुए उन्होंने कहा, 'जो काम हो रहा उसमें अकेले मेरा क्रेडिट नहीं है, इसमें मेरे सेक्रेटरी से लेकर विभाग के हर आदमी का योगदान है। मुंबई दिल्ली हाइवे पर हमने 2.5 किलोमीटर 4 लेन का कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया है। मुझे लगता है कि ये रेकॉर्ड इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं।' गडकरी ने कहा, 'पर कभी कभी मेरी भूमिका माता-पिता के जैसे होती है, जैसे वे कहते हैं कि 75 मार्क क्यों मिले, 85 क्यों नहीं मिले? मैं कहता हूं कि एक बार फाइनैंशल ऑडिट न हो चलेगा लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां कमियां लगती हैं जो काम नहीं करते हैं उन लोगों को मैं जरूर डांटता हूं। उसके पीछे मेरी भावना यही रहती है कि जल्द से जल्द काम हो।'

देशभर के जैविक किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों की उपस्थिति में हुआ आर्गेनिक एक्सपो 2021 का शानदार आगाज

फैमिली फार्मर व फैमिली काऊ योजना का शुभारम्भ

इंदौर। मिशनहेल्दीइंडिया के तहत देश के सबसे बड़े ऑर्गनिक मेले का आगाज आज इंदौर के कृषि महाविद्यालय में हो गया है। 21 मार्च तक चलने वाले इस पांच दिवसीय जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन- आर्गेनिक एक्सपो 2021 का शुभारम्भ श्री कमल सिंह अंजना, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, मालवा प्रान्त, श्री साईं प्रसाद, निदेशक, भारतीय गेंहू कृषि अनुसंधान केंद्र, मप्र छत्तीसगढ़ , आलोक मीणा, संयुक्त संचालक, कृषि, डॉ अशोक शर्मा, डीन, कृषि महाविद्यालय, श्री लक्ष्मी नारायण पटेल, कोषाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ एवं महिला सशक्तिकरण की मिसाल सुभद्रा खापर्डे जी, ऑर्गनिक एक्सपो संचालक मनोज मिश्रा व अन्य की उपस्थिति में द्वीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस दौरान मुख्य अथिति सुभद्रा खापर्डे ने जंगल अधिकार, भू-अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण-संवर्धन, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीनीकरणीय ऊर्जा एवं देसी प्राकृतिक खेती पर तेजी से काम जारी रखने के साथ जैविक को अपनाने के विशेष कारणों पर भी ध्यान आकर्षित किया। जबकि मुख्य आयोजनकर्ता श्री मनोज मिश्रा ने फैमिली फार्मर व फैमिली काऊ योजनाओं की घोषणा करते हुए, सभी से जैविक बनने का आग्रह किया। वहीँ व्यापारी व ट्रेनर आकाश चौरसिया ने आर्गेनिक मल्टी लेयर फार्मिंग पर उद्बोधन देकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।

इस प्रदर्शनी में जैविक कम्पनियों के स्टाल तथा जैविक कृषि कर रहे किसानों के उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय किया जा रहा है। जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जैविक खेती के साथ आर्गेनिक उत्पादों के अधिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। यहाँ आपको घी, तेल नमक मसाले, पूजा पाठ सामग्री से लेकर फल व सब्जियों तक, सब कुछ जैविक खेती से तैयार किया हुआ ही मिलेगा। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम में ज्ञान सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत जैविक क्षेत्र की महान विभूतियां जैसे सुश्री शर्मिला जैन, श्री रमेश भाई रूपरेलिया, श्री गोपाल भाई सुतरिया व अन्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा।

गौरतलब है कि एक्सपो के आगामी दिनों में गौ आधारित जैविक खेती का सजीव प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। जहां उन्नत किस्म के पशुओं की प्रदर्शनी, गोबर, गौमूत्र व फसल अवशेष के माध्यम से निर्मित विभिन्न प्रकार की जैविक खादों की प्रदर्शनी तथा जैविक सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्माण की विधि का सजीव प्रदर्शन भी होगा। इसके अतिरिक्त मेले में पहुंचने वालों के लिए जैविक सब्जी मंडी एवं फूड ज़ोन भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

बिजली कंपनी कर रही सत्रह हजार करोड़ के बजट की तैयारी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मप्रपक्षेविविकं वर्ष 2021-22 के लिए बजट तैयार कर रही है, यह लगभग 17 हजार करोड़ का होगा। कंपनी मालवा और निमाड़ के लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराती है। इस बार बजट में बिजली खरीदी, नए कार्य, सुरक्षा, मैंटनेंस, प्रशिक्षण, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, कर्मचारी हितों, ग्रिडों की स्थापना आदि के लिए पर्याप्त निधि रहेगी। बजट की तैयारी के लिए बुधवार को प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने विशेष बैठक बुलाई। इसमें मुख्य महाप्रबंधक श्री संतोष टैगोर. निदेशक श्री मनोज झंवर, कार्यपालक निदेशक श्री संजय मोहासे, श्री गजरा मेहता मुख्य वित्त अधिकारी श्री नरेंद्र बिवालकर, उपनिदेशक बजट डॉ. शैलेष कर्दम आदि मौजूद थे। सभी विभागाध्यक्षों ने अपने कार्यक्षेत्र की प्राथमिकताओं एवं व्यय आदि पर चर्चा की।

मालवा-निमाड़ में अब तक 2461 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति

पिछले वर्ष की तुलना में 4.5 फीसदी और 105 करोड़ यूनिट ज्यादा वितरण

प्रबंध निदेशक कर रहे दैनिक समीक्षा

इंदौर। पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने जारी वित्तीय वर्ष में बिजली वितरण के अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए है। जारी वित्तीय वर्ष के साढ़े 11 माह के दौरान मालवा-निमाड़ में कंपनी 2461 करोड़ यूनिट बिजली वितरित की है। यह गत वर्ष से लगभग 4.5 फीसदी एवं 105 करोड़ यूनिट अधिक है। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि 1अप्रैल 2020 से लेकर 16 मार्च 2021 तक के आंकड़ों में साढ़े चार फीसदी ज्यादा बिजली वितरित हुई है। इस दौरान वर्ष 2019-20 में कुल 2355 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हुआ था। वर्ष 2020-21 के दौरान 2461 करोड़ यूनिट की आपूर्ति हुई है। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि इंदौर जिले में इस दौरान लगभग 425 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हुआ है। धार जिले में लगभग 300 करोड़ यूनिट, उज्जैन में 268 करोड़ यूनिट, खरगोन में 245 करोड़ यूनिट, देवास में 218 करोड़ यूनिट, रतलाम में 170 करोड़ यूनिट बिजली का वितरण हुआ है। शेष जिलों में 56 करोड़ यूनिट से लेकर 131 करोड़ यूनिट की आपूर्ति जारी वित्तीय वर्ष के इन साढ़े 11 माह के दौरान हुई है। श्री तोमर ने बताया कि वर्ष में दो दिन ऐसे रहे , जहां कंपनी स्तर पर दैनिक आपूर्ति दस करोड़ यूनिट से ज्यादा रही। वर्षभर की औसत दैनिक आपूर्ति 7 करोड़ यूनिट रही, वहां पिछले चौबीस घंटों की आपूर्ति 7.55 करोड़ यूनिट दर्ज की गई। प्रबंध निदेशक ने बताया कि कंपनी स्तर पर आपूर्ति की दैनिक समीक्षा होती है, जहां भी मैंटनेंस, स्थानीय प्रशासन की मांग या अन्य कारण, आपदा संबंधी परेशानी होती है, वहां तुरंत ही इंजीनियरों की टीम को संसाधनों के साथ भेजकर समाधान कराया जाता है।

इंदौर ने भी तोड़े रिकार्ड

प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि मार्च 2021 में इंदौर शहर में भी आपूर्ति का रिकार्ड टूटे है। यहां पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 86 लाख यूनिट की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति की गई। मार्च के पांच दिनों में इंदौर की मांग रिकार्ड स्तर पर 80 लाख से ज्यादा रही। मार्च में किसी भी वर्ष में औसत दैनिक मांग 70 लाख यूनिट से ज्यादा नहीं देखी गई थी।

OPEC देशों को झटका देने के तैयारी में भारत

Saudi Arabia से तेल आयात में होगी कटौती

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच भारत सऊदी अरब सहित तेल उत्पादक देशों (OPEC+) को झटका देने की तैयारी में है। कच्चे तेल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार लगातार ओपेक देशों के साथ बातचीत कर रही थी और उनसे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने की अपील की जा रही थी। लेकिन काफी मान-मनौव्वल के बाद भी जब कच्चे तेल की कीमत (ण्ल् दग्त ज्ग्मे) कम करने के लिए सऊदी अरब सहित ध्ईंद्ध देश नहीं माने तो भारत ने सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करने का फैसला किया है। OPEC+ देशों द्वारा कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती करने के फैसले से कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंचा है। इस वजह से भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने अमेरिका से अधिक से अधिक तेल आयात करने का फैसला किया है, जिनकी कीमतें कम हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी क्रूड ऑयर हल्का होता है और इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। भारत चीन और जापान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की स्टेट रिफाइनरीज ने सऊदी अरब से तेल के आयात को कम करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मई तक सऊदी अरब से तेल आयात को एक चौथाई कम कर दिया जाएगा। दरअसल, मोदी सरकार ने विनती से बात नहीं बनने पर नए विकल्प पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार अब तेल के लिए मिडिल ईस्ट देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारत की रिफाइनरी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल रोजाना है। इसमें 60 फीसदी कंट्रोल स्टेट रिफाइनरी के पास है। ये सरकारी तेल कंपनियां करीब 14.8 मिलियन बैरल तेल एक महीने में सऊदी अरब से आयात करती हैं। मई तक इसे घटाकर 10.8 मिलियन बैरल पर लाने की योजना है।

अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक

भारत ने अब अमेरिका से तेल आयात को बढ़ा दिया है जिसके कारण सऊदी अरब को पीछे छोड़ अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया है। फरवरी में अमेरिका से भारत को तेल निर्यात 48 फीसदी बढ़ा और यूएस अब भारत को रोज 5.45 लाख बैरल तेल निर्यात कर रहा है। यह भारत के कुल आयात का 14 फीसदी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (ध्ध्प्) ने पश्चिम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और कनाडा से क्रूड ऑयल मंगाने के लिए टेंडर जारी किया है। आपको बता दें कि जनवरी में सऊदी अरब से भारत का तेल आयात 36ज्ञ गिर गया। जबकि अमेरिका से तेल आयात लगभग दोगुना हो गया है। पिछले साल भारत ने अपनी जरूरत का 86ज्ञ तेल ध्ईंद्ध देशों से आयात किया था, जिसमें 19ज्ञ सऊदी अरब से आया था।

अब झट से क्लियर होगा चेक, RBI का सभी बैंकों को CTS लागू करने का आदेश

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से 30 सितंबर तक बाकी सभी ब्रांचेज में इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) लागू करने को कहा है।

इस कदम से चेकों का सेटलमेंट तेजी से हो सकेगा और कस्टमर सर्विस में सुधार होगा। अब भी 18,000 बैंक ब्रांचेज ऐसी हैं जो औपचारिक चेक क्लियरिंग सिस्टम से अलग हैं। चेक की इमेज पर आधारित ट्रंकेशन सिस्टम में चेकों को फिजिकल रूप से एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने की जरूरत कम या खत्म हो जाती है। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने पूरे देश के स्तर पर सीटीएस को लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत सभी बैंक ब्राचेंज को इमेज आधारित सीटीएस व्यवस्था के तहत लाया जाएगा। सीटीएस का इस्तेमाल 2010 से हो रहा है। अभी 1,50,000 बैंक ब्रांचेज इसके तहत आती हैं। सभी पूर्ववर्ती 1,219 ईसीसीएस केंद्र सितंबर, 2020 से सीटीएस के तहत ट्रांसफर हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई बैंक ब्रांचेज अब भी औपचारिक सीटीएस व्यवस्था से बाहर हैं। उनके ग्राहकों को इसकी वजह से काफी परेशानी होती है। उनका चेक निकलने में अधिक समय लगता है।

रिजर्व बैंक के सर्कुलर में कहा गया है कि सीटीएस की उपलब्धता के इस्तेमाल तथा सभी ग्राहकों को समान अनुभव प्रदान करने के लिए सीटीएस को देशभर में सभी बैंक शाखाओं में लागू करने का फैसला किया गया है। इसके तहत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर, 2021 तक उसकी शाखाएं इमेज आधारित सीटीएस प्रणाली के तहत आ जाएं। इसके लिए बैंक कोई भी मॉडल अपनाने को स्वतंत्र होंगे। बैंक इसके लिए प्रत्येक शाखा में उचित ढांचा लगा सकते हैं या फिर हब या स्पोक मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सेंटर फ्रेश मिन्ट्स 'क्लीन ब्रेथ' के लॉन्च के साथ सेंटर फ्रेश ने ब्रांड पोर्टफोलियो को मजबूत किया

यह अनोखा प्रोडक्ट ब्रांड के तीव्र मिंट श्रेणी में प्रवेश को चिन्हित करता है देश में एकमात्र सुगर-फ्री मिंट 1 जो रुपये में उपलब्ध है

इन वर्षों में, कन्फेक्शनरी प्रमुख परफेक्ट्री वैन मेलले इंडिया का प्रतिष्ठित ब्रांड सेंटर फ्रेश ताज़ा सांस का पर्याय बन गया है, जिससे लोगों को सामाजिक परिस्थितियों में संलग्न होने के लिए सक्षम बनाया गया है। इस वादे को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रांड ने सेंटर फ्रेश मिन्ट्स 'क्लीन ब्रेथ' लॉन्च किया है, जिसके साथ ही ब्रांड ने 'इंटेंस मिन्ट्स सेगमेंट' में अपनी उपलब्धता को चिन्हित किया है। सेंटर फ्रेश मिन्ट्स 'क्लीन ब्रेथ' एक 3-परत उत्पाद है जिसे केंद्रीय परत में ट्रैप्ड जिंक लैक्टेट के साथ कंप्रेस्ड मिंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है। यह मेंथॉल युकलिप्टस फ्लेवर में उपलब्ध है और, यह उत्पाद गहन शीतलन और ताजगी प्रदान करने के लिए चिकित्सकीय रूप से सिद्ध है जो 60 मिनट तक रहता है। यह पेशकश एक अद्वितीय और आकर्षक तितली के आकार में उपलब्ध है जो जीभ की सफाई में सहायता करने वाली लकीरों के साथ-साथ मुंह में आसानी से घूमने की अनुमति देता है। 1 रुपए की कीमत पर उपलब्ध, यह अनोखा प्रोडक्ट देश का पहला सुगर-फ्री मिंट है जो इस आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध है। 'सेंटर फ्रेश मिन्ट्स क्लीन ब्रेथ' उन पेशेवरों को लक्षित करता है, जिन्हें कार्यस्थल पर उच्च-स्तरीय स्थितियों में लेने के लिए तीव्र ताजा सांस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए, घर से काम करने के लगभग एक साल के बाद बाहर जाने वाले उपभोक्ताओं के साथ इसके लॉन्च का समय सठिक है। नए लॉन्च पर बोलते हुए, परफेक्ट्री वैन मेलले इंडिया के डायरेक्टर मार्केटिंग, रोहित कपूर ने कहा, 'पिछले ढाई दशकों में, हम सभी अवसरों के लिए उपयोगी उत्पादों की पेशकश करने के लिए विभिन्न उपभोग प्रवृत्तियों का लाभ उठाकर सेंटर फ्रेश के लिए एक मजबूत प्रतिध्वनि पैदा करने में सक्षम रहे हैं। जैसे-जैसे लोग काम और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए बाहर निकलना शुरू करते हैं, उन्हें फ्रेश और आत्मविश्वास महसूस करने की आवश्यकता होगी। क्लीन ब्रेथ हमारे उपभोक्ताओं के लिए एक लंबी अवधि के लिए ताजा सांस आत्मविश्वास प्रदान करता है। हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्लीन ब्रेथ ब्रांड में वृद्धिशील व्यापार को मजबूती देगा। यह लॉन्च हमारी स्थानीय विशेषज्ञता और अनुभव के साथ हमारी वैश्विक विशेषज्ञता और नवीनता को एक साथ लाता है।' टीवीसी पर टिप्पणी करते हुए, अनुराग अग्निहोत्री, मैनेजिंग पार्टनर - क्रिएटिव (पश्चिम), ओगिल्वी ने कहा, 'हमारे लिए बड़ी खबर यह थी कि सेंटर फ्रेश मिंट क्लीन ब्रेथ 60 मिनट की ताजी सांस देता है। । हमने जो कट लिया, वह 60 मिनट का आत्मविश्वास था।फिल्म 'गुड लक चार्म्स' के खिलाफ सीधे तौर पर क्लीन ब्रेथ प्रपोजल पेश करके इसे एक आकर्षक तरीके से पेश करती है, जिसे लोग हाई-स्टेक स्थिति में देखते हैं।' लॉन्च टीवी पर अभियान, बड़े पैमाने पर डिजिटल माध्यम पर और खुदरा व्यापार के लिए बिक्री सामग्री के बिंदु के साथ समर्थित है। टीवीसी एक युवा के बारे में है जो नौकरी के लिए साक्षात्कार का इंतजार कर रहा है। स्थिति के कारण वह स्पष्ट रूप से घबरा गया। लेकिन जब एक फूल कहीं से उसके सिर पर गिरता है, तो वह इसे सौभाग्य की निशानी के रूप में लेता है और आत्मविश्वास महसूस करता है। यह आत्मविश्वास हालांकि उस क्षण को दर्शाता है, जब वह साक्षात्कार कक्ष में चलता है और वह साक्षात्कारकर्ताओं का सामना किए बिना चला जाता है। फिर हम एक ही कहानी को फिर से देखते हैं लेकिन इस बार, एक फूल के बजाय, वह सेंटर फ्रेश मिन्ट्स क्लीन ब्रेथ का एक पैकेट पाता है और उसे पॉप करता है। इस बार वह पूरी दम के साथ साक्षात्कार में सफल होता है क्योंकि 60 मिनट तक चलने वाले उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली स्थितियों में लाभ प्राप्त करते हैं। वह स्पष्ट रूप से साक्षात्कारकर्ताओं पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है और नौकरी ले लेता है। फिल्म को एक ट्रैक द्वारा भी समर्थन दिया जाता है जो फिल्म को उत्तेजित करता है ताकि उत्साह को जीवित रखा जा सके।

15 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यु कराना होगा महंगा

एजेंसी। पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाइवे मिनिस्ट्री ने आज 17 मार्च को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्युअल की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। रोड मिनिस्ट्री ने सेंट्रल मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) रूल्स, 2021 जारी किया है। यह 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। इस रूल्स के तहत प्रस्ताव रखा गया है कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर अब पहले से ज्यादा फीस देनी होगी।

कितनी होगी फीस?

15 साल से पुरानी दोपहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर 1000 रुपए की फीस देनी होगी। वहीं तिपहिया और चार पहिया गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए 3500 रुपए की फीस चुकानी होगी। लाइट मोटर व्हीकल्स का रिन्युअल चार्ज बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया गया। ठीक इसी तरह मीडियम गुड्स या पैसेंजर मोटर व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट देने और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल कराने के लिए फीस बढ़ाकर 12,500 रुपए देने होंगे। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायरी एक्सपायरी होने के बाद अप्लाई किया जाता है तो प्रति दिन के हिसाब से 50 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। सरकार ने यह प्रस्ताव ऐसे समय में पेश किया है जब इस साल बजट में वॉलेन्ट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू किया गया था। इसके तहत पर्सनल व्हीकल का फिटनेस टेस्ट 20 साल के बाद होगा। जबकि कमर्शियल व्हीकल्स का फिटनेस टेस्ट 15 साल के बाद होगा। 15 साल पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का रिन्युअल 5 साल तक वैध रहेगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अब पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, मैनुअल मोटरसाइकिल के लिए 400 रुपए चुकाना होगा। वहीं ऑटोमेटेड बाइक के लिए 500 रुपए चुकाने होंगे।मैनुअल लाइट व्हीकल और तिपहिया वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए 800 रुपए लगेगा। वहीं ऑटोमेटेड वर्जन गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट पर 1,000 रुपए खर्च करना होगा। 15 साल पुराने मैनुअल मीडियम गुड्स और पैसेंजर व्हीकल्स के के फिटनेस टेस्ट के लिए 800 रुपए देने होंगे। जबकि ऑटोमेटेड गाड़ियों के लिए 1300 रुपए देने होंगे। हेवी गुड्स और पैसेंजर व्हीकल्स के फिटनेस टेस्ट पर 1000 रुपए चार्ज लगेगा। जबकि ऑटोमेटेड व्हीकल्स के फिटनेस टेस्ट के लिए 1500 रुपए देने होंगे।

आईसीआईसीआई वेंचर एवं मोर्गन स्टैंली पीई एशिया ने मैग्मा एचडीआई में 525 करोड रुपए का ट्रांजैक्शन किया

मुंबई। मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (मैग्मा एचडीआई) ने एक ट्रांजैक्शन की घोषणा की है जिसमें कंपनी में नए शेयरधारकों के रूप में दो फैमिली ऑफिस और साइजा केम प्रा. लि. (पूनावाला ग्रुप की कंपनी) के साथ आईसीआईसीआई वेंचर और मोर्गन स्टेनली प्रा. इक्विटी एशिया द्वारा संचालित फंड लाने का समावेश है. 525 करोड रुपए के ट्रांजैक्शन में 250 करोड़ रुपए की प्राथमिक पूंजी जुटाने का समावेश है.

250 करोड़ रुपए की नई पूंजी कंपनी की वितरण क्षमता बढ़ाने की जरूरत पूरी करने के लिए ग्रोथ पूंजी । प्रदान करेगी. 275 करोड़ रुपए की सेकेंडरी बिक्री मैग्मा फिनकॉर्प और उसकी ग्रुप कंपनियों को बीमा कंपनियों में स्वामित्व हिस्सा प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में समर्थ बनाएगी.

यह ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईआरडीएआई) और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) सहित शेयरधारकों एवं नियामक मंजूरियों के अधीन है.

श्री राजीव कुमारस्वामी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर, मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस ने पूंजी जुटाने पर टिप्पणी करते हुए कहा, ' हम कंपनी में नए शेयरधारकों का स्वागत करते हुए हर्षित है और हमारे मौजूदा शेयरधारकों के निरंतर सपोर्ट की सराहना करते हैं. निवेशकों द्वारा कंपनी में लाई गई ग्रोथ पूंजी हमें कारोबार बढ़ाने और नए अवसरों का उपयोग करने में समर्थ बनाएंगी. बीमा क्षेत्र कम पैठ और महामारी के फैलाव को देखते हुए भारी ग्रोथ के लिए सुसज्जित है. जिसने लोगों को सुरक्षा के रूप में बीमा क्षेत्र को देखने के लिए विवश किया है.'

श्री अदार पूनावाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर, सिरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया ने कहा, ' हम मैग्मा एसडीआई के शेयरधारक के रूप में हमारे निरंतर सपोर्ट के लिए हर्षित है और मैग्मा एसडीआई में भारी संभावना देख रहे हैं, जो युवा एवं तेजी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है. हमें विश्वास है कि आगामी कुछ वर्षों में यह अपनी पूर्ण संभावना पर पहुंचेगी.'

श्री अभय भूटाडा, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफीसर, पूनावाला फाइनेंस ने कहा, 'हम बीएफएसआई क्षेत्र में बढ़ते हुए सुअवसर को लेकर अति उत्साहित है और बड़े निवेशकों द्वारा मैग्मा एसडीआई में पूंजी डालने और बीमा कंपनी में पूनावाला ग्रुप द्वारा सीधे हिस्से में और वृद्धि किए जाने से कंपनी अच्छी तरह पूंजी कृत होने के साथ लाभप्रद ग्रोथ और अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए सुसज्जित है.'

श्री संजय चामरिया, वाइस चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैग्मा फिनकॉर्प लि. ने कहा, ' मैग्मा एचडीआई ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और उच्च क्वालिटी के निवेशकों के आने और पूनावाला ग्रुप द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूंजी डालने से कंपनी अपनी पूर्ण संभावना का दोहन करने और जीआई उद्योग में अपना खास स्थान बनाने के लिए तैयार है.'

श्री पुनीत नंदा, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आईसीआईसीआई वेंचर ने कहा, ऊ 'हम अल्प पैठ वाले भारतीय बीमा क्षेत्र द्वारा ऑफर की गई संभावनाओं के बारे में अति उत्साहित है. मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस के बोर्ड और टीम के साथ कार्य करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भारतीय ग्राहकों की सुरक्षा की जरूरत पूरी करते हुए भारतीय जीआई मार्केट में स्थान बनाने के इच्छुक

श्री नीरव मेहता, मॉर्गन स्टेनली प्राइवेट इक्विटी एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, 'भारत में जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र ढांचागत ग्रोथ के लिए तैयार है और हमारा मानना है कि मैग्मा एचडीआई उसकी मैनेजमेंट मजबूती, सावधानीपूर्वक प्रोडक्ट चयन, विश्वसनीय अंडरराइटिंग और वितरण नेटवर्क वह दिए गए इस अवसर लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह तैयार है. हम मैग्मा एसडीआई के साथ उसके विकास के आगामी चरण में सहयोग करने के इच्छुक है.' मैग्मा एसडीआई जनरल इंश्योरेंस गत 3 वर्ष से 45% सीएजीआर के साथ एक सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली जीआई कंपनी है. 31 दिसंबर 2020 को कंपनी की सॉल्वेंसी 1.5 गुना अपेक्षित नियामक सॉल्वेंसी की तुलना में 1.81 गुना थी. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वित्त वर्ष 21 के प्रथम 9 महीने में 911.2 करोड़ रुपए की जीडब्ल्यूपी पर 22.3 करोड़ रुपए का कर बाद लाभ प्राप्त किया जबकि गत वर्ष की समान अवधि में 948.5 करोड़ रुपए की जीडब्ल्यूपी पर 7.3 करोड़ रुपए का कर बाद लाभ हुआ था. दिसंबर 2020 को निवेश बुक 2881 करोड़ रुपए के मजबूत स्तर पर थी. एमबिट प्राइवेट लिमिटेड ट्रांजैक्शन के विशेष वित्तीय सलाहकार और वाडिया घांडी कानूनी सलाहकार है।

ब्रजमंडल में होली की धूम

जानिए बरसाने की होली की 5 खास बातें

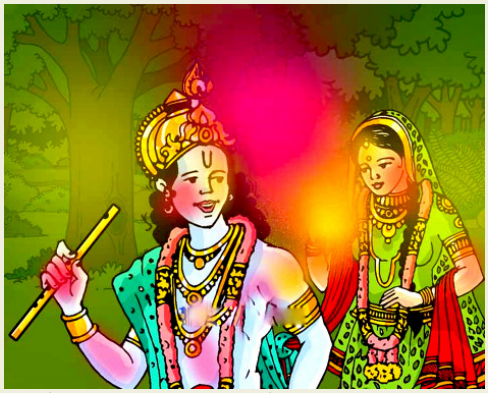

ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन, नंदगाव आदि कई गांव आते हैं। यहां पर वसंत पंचमी से ही होली के उत्सव की धूम शुरु हो जाती है। ब्रजमंडल में खासकर मथुरा में लगभग 45 दिन के होली के पर्व का आरंभ वसंत पंचमी से ही हो जाता है। बसंत पंचमी पर ब्रज में भगवान बांकेबिहारी ने भक्तों के साथ होली खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है।

1. भारत में कई जगह तो फाल्गुन मास प्रारंभ होते ही होली का डांडा रोपड़ कर होली उत्सव का प्रारंभ हो जाता है तो कई जगहों पर होलाष्टक पर डांडा रोपड़कर इस उत्सव की शुरुआत की जाता ही। ब्रज मंडल में फाग उत्सव के बाद होलिका दहन और फिर धुलेंडी अर्थात धूलिवंदन मनाया जाता है। इस दिन लोग एक-दूसरे से गले मिलते हैं। मिठाइयां बांटते हैं। भांग का सेवन करते हैं। होलिका दहन के ठीक पांचवें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है।

2. ब्रज मंडल में होली सबसे ज्यादा धूम बरसाने में रहती है। विश्वविख्यात है बसराने की होली। इस होली को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यहां कई तरह से होली खेलते हैं, रंग लगाकर, डांडिया खेलकर, लट्ठमार होली आदि।

3. ब्रज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन होली का डांडा गढ़ जाता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रीजी मंदिर में राधारानी को 56 भोग का प्रसाद लगता है। अष्टमी के दिन नंदगांव व बरसाने का एक-एक व्यक्ति गांव जाकर होली खेलने का निमंत्रण देता है। नवमी के दिन जोरदार तरीके से होली की हुड़दंग मचती है। नंदगांव के पुरुष नाचते-गाते छह किलोमीटर दूर बरसाने पहुंचते हैं। इनका पहला पड़ाव पीली पोखर पर होता है। इसके बाद सभी राधारानी मंदिर के दर्शन करने के बाद लट्ठमार होली खेलने के लिए रंगीली गली चौक में जमा होते हैं। दशमी के दिन इसी प्रकार की होली नंदगांव में होती है।

4. राधा-कृष्ण के वार्तालाप पर आधारित बरसाने में इसी दिन होली खेलने के साथ-साथ वहां का लोकगीत 'होरी' गाया जाता है। फाल्गुन मास की नवमी से ही पूरा ब्रज रंगीला हो जाता है, लेकिन विश्वविख्यात बरसाने की लट्ठमार होली जिसे होरी कहा जाता है, इसकी धूम तो देखने लायक ही रहती है। देश-विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी।

5. इस दिन कृष्ण के गांव नंदगांव के पुरुष बरसाने में स्थित राधा के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं लेकिन बरसाने की महिलाएं एकजुट होकर उन्हें लट्ठ से खदेड़ने का प्रयास करती हैं। इस दौरान पुरुषों को किसी भी प्रकार के प्रतिरोध की आज्ञा नहीं होती। वे महिलाओं पर केवल गुलाल छिड़ककर उन्हें चकमा देकर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है और उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर श्रृंगार इत्यादि करके सामूहिक रूप से नचाया जाता है।

होलाष्टक की पौराणिक कथा

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होली दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है। इस बार 22 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 तक होलाष्टक रहेगा। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को किया जाएगा और इसके बाद अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। आओ जानते हैं होलाष्टक की पौराणिक कथा।

होलाष्टक के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। पहली कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी है और दूसरी कथा कामदेव से

1. पहली कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उनका ध्यान अपनी और करने के लिए लगातार 8 दिनों तक उन्हें तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि, होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वहीं होलाष्टक के दिन है। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाता है तो उसकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है।
2. दूसरी कथा के अनुसार देवताओं के कहने पर शिवजी की तपस्या भंग करने के कारण जब कामदेव को शिवजी अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं तब कामदेव की पत्नि शिवजी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती है। रति की भक्ति को देखकर शिवजी इस दिन कामदेव को दूसरा जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन दे देते हैं। कामदेव बाद में श्रीकृष्ण के यहां प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं।

14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे सूर्यदेव, इस राशि वालों के लिए प्रमोशन, वेतनवृद्धि के योग

14 मार्च रविवार से मलमास या खरमास लग गया। इसके पीछे कारण है सूर्य का राशि परिवर्तन। ज्योतिषार्यों के अनुसार, 14 मार्च को शाम 6 बजकर 4 मिनट पर सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर लिया। वे 14 अप्रैल को सुबह 2 बजकर 33 मिनट तक इस स्थिति में रहेंगे। सूर्य का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर असर डालेगा। बता दें, ज्योतिष विज्ञान में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। कुंडली में सूर्य की स्थिति को उच्च पद,यश, नेतृत्वकर्ता, सत्ता आदि से जोड़कर देखा जाता है।सूर्य के शुभ होने पर जातक की जिंदगी बन जाती है, वहीं अशुभ होने पर अपयश, हृदय रोग और आंखों से जुड़े रोग होते हैं। जानिए सूर्य के राशि परिवर्तन का राशियों पर होने वाले असर के बारे में

मेष राशिः सूर्य के इस राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों के आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा। ऑफिस में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। काम के प्रति अपनी ईमानदारी जारी रखें।

वृष राशिः सूर्य का यह गोचर वृष राशि वालों के लिए शुभकारी होगी। इनकम के नए स्रोत बनेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी।

मिथुन राशिः सूर्य का मीन राशि में प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए फलदायी होगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। जॉब और बिजनेस में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रमोशन हो सकता है।

कर्क राशिः सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए धन योग बना रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अचानक धन प्राप्त होगा।

सिंह राशिः सूर्य का यह परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए मिलाजुला असर देगा। जितनी मेहनत करेंगे, उतना फल मिलेगा। मन लगाकर काम करते रहें, धैर्य बनाए रखें।

कन्या राशिः दांपत्य जीवन पर असर पड़ सकता है। खर्च पर कंट्रोल रखें। सेहत का ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। परिजन का पूरा सहयोग मिलेगा।

तुला राशिः सूर्य का यह राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेगा। शत्रु पराजित होगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होगा।

वृश्चिक राशिः शिक्षा और करियर में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधो में सफलता मिल सकती है। नई योजनाओं पर काम करेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

धनु राशिः इस राशि परिवर्तन के दौरान धनु राशि वाले विवाद की स्थिति में फंस सकते हैं। अपनी वाणी प संयम रखें। विवादों से बचने की कोशिश करें। अपनी तथा परिजन की सेहत का ख्याल रखें।

मकर राशिः मकर राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा। प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। लव लाइफ में सुधार होगा। लव पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा।

कुंभ राशिः परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों पर ध्यान दें। अपने स्वभाव और वाणी पर काबू रखें। तर्क और विवाद की स्थिति से बचने की कोशिश करें।

मीन राशिः सूर्य का राशि परिवर्तन इसी राशि में होने जा रहा है। मीन राशि वाले इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। ऑफिस में सावधानी से काम करें।

जानिए होलाष्टक के समय क्या करें और क्या नहीं

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होलाष्टक होली दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है। इस बार 22 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 तक होलाष्टक रहेगा। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को किया जाएगा और इसके बाद अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। होलाष्टक 2021 में वर्जित कार्य : विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, कोई नया कार्य प्रारंभ करना एवं अन्य प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। क्या करना चाहिए : होलाष्टक में पूजा-पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्रीसूक्त व मंगल ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ करना चाहिए जिससे आर्थिक संकट समाप्त होकर कर्ज मुक्ति मिलती है।इस दौरान भगवान नृसिंह और हनुमानजी की पूजा का भी महत्व है। होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले दिन एक स्थान पर दो डंडे स्थापित किए जाते हैं। जिनमें से एक डंडा होलिका का प्रतीक तो दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद इन डंडों को गंगाजल से शुद्ध करके के बाद इन डंडों के इर्द-गिर्द गोबर के उपले, लकड़ियां, घास और जलाने वाली अन्य चीजें इकट्ठा की जाती है और इन्हें धीरे-धीरे बड़ा किया जाता है और अंत में होलिका दहन वाले दिन इसे जला दिया जाता है।

सोने में फिर लौट रही तेजी

44500 के पार गई प्रति 10 ग्राम की कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने की कीमत में फिर से उछाल आ रहा है। बुधवार को भी सोने में तेजी आई और दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 60 रुपये तेज होकर 44,519 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। ष्ठ्रङ्ग सिक्योरिटीज के मुताबिक, वैश्विक बाजारों में सोने की मजबूत कीमतों और रुपये में गिरावट से घरेलू बाजार में सोने की कीमत को बल मिला। पिछले ट्रेड में सोने का हाजिर भाव 44,459 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी में सोने से अलग रुख देखने को मिला। बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 200 रुपये टूटकर 66,536 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले ट्रेड में यह 66,736 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

वैश्विक भाव में कितनी तेजी

सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों की बात करें तो बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1,735 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। वहीं चांदी 26 डॉलर प्रति औंस पर फ्लैट थी। सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों का असर भारत में इन कीमती धातुओं की कीमतों पर भी दिखता है।

वायदा बाजार में क्या रहा सोने का हाल

मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोना 140 प्रतिशत की तेजी के साथ 44,953 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल महीने में डिलीवरी वाले सोना वायदा की कीमत 140 रुपये यानी 0.31 प्रतिशत की तेजी के साथ 44,953 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें 8,942 लॉट के लिये कारोबार किया गया।

चांदी वायदा की कीमत

मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया, जिससे वायदा बाजार में बुधवार को चांदी वायदा कीमत 246 रुपये की तेजी के साथ 67,165 रुपये प्रति किलो हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के मई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 246 रुपये यानी 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 67,165 रुपये प्रति किलो हो गई, जिसमें 12,014 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

रिकॉर्ड हाई से 22% से भी ज्यादा टूट चुका है सोना

सोना खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए इस वक्त सुनहरा मौका चल रहा है। सोने का हाजिर भाव इसके रिकॉर्ड हाई से 22 फीसदी नीचे आ चुका है। अगस्त 2020 में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 57008 रुपये प्रति 10 ग्राम के मार्क पर पहुंच गया था। यह सोने का अब तक का उच्च स्तर है। लेकिन अब सोने का हाजिर भाव रिकॉर्ड हाई से 12527 रुपये गिरकर काफी नीचे आ चुका है।

2020 में आई तगड़ी तेजी

2020 में सोने के दाम में तगड़ी तेजी की वजह कोरोना वायरस रहा, जिसकी वजह से लोग निवेश का सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे थे। सोने में निवेश हमेशा से ही सुरक्षित रहा है। कोरोना की वजह से शेयर बाजार में लोगों ने निवेश कम कर दिया, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश रिस्की होता है। पिछले साल जनवरी-फरवरी में तो सोना धीरे-धीरे बढ़ रहा था, लेकिन मार्च में भारत में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद इसने स्पीड पकड़ ली।

बजट ऐलान के बाद लगातार आई गिरावट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021 के अपने प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क (import tax) में भारी कटौती की घोषणा की थी। सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की कटौती की है। अब सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी के बजाय सिर्फ 7.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी। इस घोषणा के बाद से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आ रही है। भारत बड़े पैमाने पर सोने का आयात करता है। चीन के बाद भारत सोने का सबसे बड़ा खरीदार है।

बीच में थोड़े समय के लिए फिर बढ़ सकती है सोने की चमक

महामारी से प्रभावित अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 1.9 लाख करोड़ डॉलर का पैकेज घोषित किया जा चुका है। उम्मीद है कि सरकार इसे जल्द ही मंजूरी भी प्रदान कर दे। इसके बाद सोना फिर से चमक सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो यह चमक ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह पाएगी और सोने का दाम फिर से नीचे आ जाएगा। वहीं, अप्रैल से शादी का सीजन शुरू होने से भी सोना थोड़ा मंहगा हो सकता है, लेकिन मामूली तौर पर ही।

31 मार्च तक निपटा लें ये सात काम, वरना बाद में होंगे परेशान

एजेंसी। एक अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। नया वित्त वर्ष हमारे और आपके जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आता है जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। इनकम टैक्स से लेकर एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक के कुछ फायदे उठाने और काम करने के लिए 31 मार्च तक का समय दे रहे हैं। अगर 31 मार्च से पहले आपने वो काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए जा रहे सबसे सस्ते होम लोन से भी वंचित हो सकते हैं। आइए जानते हैं 31 मार्च तक कौनसे काम निपटाने हैं।

ICICI बैंक का सबसे सस्ता होम लोन 31 मार्च तक

आईसीआईसीआई बैंक ने होम लोन की ब्याज दर 6.70 फीसदी तक घटाने की घोषणा की है। ग्राहक इस ब्याज दर का लाभ 75 लाख तक के होम लोन के लिए उठा सकते हैं, जबकि 75 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए ब्याज दरों को 6.75 फीसदी पर आंका जाता है। बैंक ने कहा कि ब्याज दर की पेशकश, 31 मार्च तक वैध है। यह इस दशक की सबसे निचली दर है।

PNB के ग्राहक 31 मार्च तक कर लें यह जरूरी काम

अगर आप देश के दूसरे सबसे बड़ सरकारी बैंक पीएनबी के खाताधारक हैं तो आपको 31 मार्च तक कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे वरना आपका लेन-देन लटक सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा। यानी 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा।

SBI दे रहा है 6.7% पर 75 लाख का होम लोन

एसबीआई होम लोन पर बड़ा ऑफर दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने 31 मार्च तक होम लोन लेने वाले ग्राहकों के प्रोसेसिंग फीस पर 100ङ्ग की छूट के साथ 6.7ङ्ग से शुरू होने वाली ब्याज दरों के साथ 70 बीपीएस (आधार अंक) तक की छूट देने की घोषणा की है। लोन की रकम, ब्याज और प्रोसेसिंग फीस की माफी आवेदक के ष्ठ्ठ्ठ स्कोर के पर निर्भर करेगा। जो लोग होम लोन का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बैंक के ष्ठ्ठ्ठ ऐप से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन के लिए आवेदन करने के लिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

पीएम किसान में 31 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या अब बढ़कर 11 करोड़ 69 लाख हो गई है। इसके तहत मोदी सरकार सलाना 6000 रुपये दो-दो हजार की तीन किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वे अगर 31 मार्च से पहले ओवदन कर देते हैं और यदि उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2000 रुपये मिलेंगे ही साथ में अप्रैल या मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये और मिल जाएंगे।

KCC पाने का 31 मार्च तक आसान मौका

अगर आप किसान हैं और अबतक आपका किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) नहीं बन पाया है तो निराश न हों। सरकार 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। जिन किसानों को अभी तक केसीसी नहीं मिला है, वे अपने नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने केसीसी प्राप्त करने के प्रॉसेसे को बेहद सरल बना दिया है। अब किसानों को एक बेहद आसान फॉर्म भरना होगा और 15 दिनों के भीतर उन्हें केसीसी प्राप्त मिल जाएगा। बता दें केसीसी लोन पर 3 लाख रुपये तक के सेवा शुल्क को माफ कर दिया गया है।

विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा 31 मार्च

आयकर विभाग ने को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास के अंतर्गत विवरण देने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च और भुगतान के लिए समय 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास कानून के तहत घोषणा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी है। बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समयसीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है। इस योजना के तहत घोषणा करने की समयसीमा 28 फरवरी थी जबकि विवादित कर राशि भुगतान की समयसीमा 31 मार्च थी।

31 मार्च 2021 के बाद क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य

सरकार ने कंपनियों से ग्राहकों (बी टू सी) के बीच लेन-देन से जुड़े बिलों के मामले में क्यूआर कोड प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाए जाने से छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए सृजित बिलों को लेकर दी गई है। हालांकि, कंपनियों के लिए जुर्माने से छूट लेने के लिए एक अप्रैल, 2021 से क्यूआर कोड प्रावधानों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

बेंटले ने उतारा बेंटाइगा एसयूवी का नया संस्करण, कीमत 4.10 करोड़ रुपये

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

ब्रिटेन की लक्जरी कार कंपनी बेंटले मोटर्स ने मंगलवार को घरेलू बाजार में बेंटाइगा एसयूवी के उन्नत संस्करण की पेशकश की, जिसकी दिल्ली में शोरूम र कीमत 4.10 करोड़ रुपये है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेंटले की नई 'बियॉन्ड 100' व्यावसायिक रणनीति के अंतर्गत पेश किया गया है। यह एसयूवी 4.0-लीटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड वी 8 पेट्रोल इंजन से लैस है। इसके अगली पीढ़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे 10.9-इंच की स्क्रीन, सुपर-हाई-रिज़ॉल्यूशन ग्राफिक्स और नाटकीय रूप से संवर्धित नेटवर्क संपर्क सुविधा के साथ लाया गया है। भारत में बेंटले के डीलर एक्सक्लूसिव मोटर्स के प्रबंध निदेशक सत्या बागला ने कहा, ''हमें भारतीय ग्राहकों के लिए नया बेंटाइगा लाने की खुशी है। बेंटले 100 से अधिक वर्षों से लक्जरी मोटर वाहन में अग्रणी है और यह नयी बेंटाइगा, बेंटले की यात्रा के अगले चरण को चिह्नित करती है।'

व्द का सबसे सस्ता प्लान, सिर्फ 3.5 रुपये में मिलता है 1GB डेटा और फ्री कॉलिंग का फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी Reliance Jio अपने ग्राहकों के लिए आए दिन धमाकेदार प्रीपेड प्लान लाती ही रहती है। यूं तो व्द के पास कम कीमत वाले कई डेटा प्लान मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्द के कुछ प्लान ऐसे हैं जिनमें आपको सिर्फ 3.5 रुपये से 4 रुपये तक की कीमत पर 1 GB डेटा मिल जाएगा। जी हां, Jio एक धमाकेदार प्लान ऑफर करता है, जिसमें ग्राहकों को 3.5 रु तक में 1 GB डेटा मिलता है। ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हर महीने रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं। आज हम आपको बात कर रहे हैं Jio के 599 रुपये वाले रिचार्ज प्लान के बारे में। इस प्लान को लेने वाले यूज़र्स को महज 3.5 रुपये खर्च कर 1GB डेटा मिलता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 84 दिन की वैलिडिटी है। बता दें कि जियो के इस 599 रुपये वाले प्लान के साथ हर दिन 2GB मिलता है। इस तरह पूरे पैके के अवधि में ग्राहकों को 599 रुपये में कुल 168 GB डेटा मिलता है। ऐसे देखा जाए तो ग्राहको को 1GB डेटा यूज करने के लिए लगभग 3.57 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

इसरो केवल नई खोजों पर ध्यान देगा, अन्य काम उद्योगों के हवाले किए जाएंगे: इसरो प्रमुख

बेंगलूरू। एजेंसी

भारतीय अंतरिक्षण अनुसंधान संगठन (इसरो) अब केवल भविष्य की नई खोजों पर ही ध्यान देगा और अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी ज्यादातर गतिविधियों को उद्योगों के हवाले कर देगा। इसरों के चेयरमैन के. शिवन ने यह जानकारी दी है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया है। शिवन अंतरिक्षण विभाग के सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल जून में इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने को लेकर सुधारों की जो शुरुआत की है उससे उद्योग जगत में काफी उत्साह जगा है। उन्होंने कहा, ''अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों का भविष्य अब बदल रहा है, अब तक अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां केवल इसरो तक की ही सीमित थी लेकिन अब इसमें निजी क्षेत्र को भी समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।''

शिवन एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन यूनिवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी स्टडीज (यूपीईएस) ने किया। उन्होंने कहा कि इसरो अपनी प्रौद्योगिकी को निजी क्षेत्र के साथ भी साझा करेगा और उन्हें अपनी सुविधाओं के इसतेमाल का अवसर भी उपलब्ध करायेगा। उन्होंने कहा, ''हम उनकी पूरी मदद करेंगे और उन्हें इसरो के स्तर तक लाने का काम करेंगे ताकि इसरो अब तक जो भी औद्योगिक प्रकृति के काम कर रहा है उन सबको उद्योगों के हवाले किया जा सके और हम भविष्य की नई खोज में अपना पूरा ध्यान लगा सकें। इससे भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के अगले स्तर तक ले जाया जा सकेगा।'' शिवन ने कहा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के लिये किये गये सुधारों के हिस्से के तौर पर निजी क्षेत्र को सभी अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा के लिये 'भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केन्द्र (इन- स्पेस) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह एक स्वायत निकाय होगा जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करेगा और अंतरिक्ष गतिविधियों के लिये, इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के मामले में नियमन और निगरानी करने वाली शीर्ष एजेंसी होगी।

भारत का हथियार आयात 33 फीसदी घटा जानें किस देश को लगा सबसे ज्यादा झटका

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत में 2011-15 और 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33 फीसदी की कमी आई है और इसका सर्वाधिक प्रभाव रूस पर पड़ा है। स्टॉकहोम के रक्षा थिंक टैंक सिपरी की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसने कहा कि देश की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने के प्रयास के तहत भारतीय हथियार आयात में कमी प्रतीत होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं ताकि सैन्य साजो-सामान के आयात पर निर्भरता कम हो सके। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा

राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 और 2020-21 के बीच करीब 1.99 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की रिपोर्ट में कहा गया, ''भारत में 2011-15 और 2016-20 के बीच हथियारों के आयात में 33 फीसदी की कमी आई। रूस सर्वाधिक प्रभावित आपूर्तिकर्ता रहा, हालांकि अमेरिका से भी भारत में हथियारों के आयात में 46 फीसदी की कमी आई।'' सरकार घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के रक्षा कारोबार का लक्ष्य रखा है। सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और चीन दोनों के हथियार निर्यात में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन द्वारा हथियारों के निर्यात में 2016-20 के दौरान 7.8 फीसदी की कमी आई है। चीनी हथियारों के बड़े खरीदारों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया थे। सिपरी ने कहा कि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और 2011-15 और 2016-20 के दौरान उसका हथियारों का निर्यात 32 फीसदी से बढ़कर 37 फीसदी हो गया।

भारत ने चालू वित्तवर्ष में 28 फरवरी तक 9.7 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने चालू वित्तवर्ष में 28 फरवरी, 2021 तक 9.7 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की वृद्धि की है। राज्यसभा को मंगलवार को यह जानकारी दी गई। बिजली और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि भारत ने अप्रैल, 2020 से फरवरी, 2021 के दौरान 9.7 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की, जिसमें 3.8 गीगावॉट पारंपरिक ऊर्जा और 5.9 गीगावॉट नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा शामिल हैं।

वर्ष 2019-20 में, भारत ने 15.8 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता की वृद्धि की थी।

अप्रैल, 2015 से फरवरी, 2021 तक, भारत ने 117.9 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता को जोड़ा है जिसमें पारंपरिक स्रोत से 64.5 गीगावॉट और अक्षय स्रोतों से 53.4 गीगावॉट बिजली शामिल है। मंत्री ने कहा, ''28 फरवरी 2021 को देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता, 379.1 गीगावॉट की है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष वित्त वर्ष (28 फरवरी, वर्ष 2021 तक) के दौरान पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल 117.9 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है। ''

कोरोना का कहर

इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीने में बंद हुए 71 लाख पीएफ अकाउंट

नई दिल्ली। एजेंसी

कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) से जुड़े लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान बंद होने वाले पीएफ अकाउंट्स (PF Accounts) की संख्या 6.5 फीसदी बढ़कर 71 लाख पहुंच गई है। 2019-20 के पहले नौ महीनों में 66.7 लाख अकाउंट बंद हुए थे। ईपीएफ अकाउंट कई कारणों से बंद होता है। इनमें रिटायरमेंट, नौकरी जाना और नौकरी बदलना शामिल है। इस समय देश में 5 करोड़ से अधिक एक्टिव ईपीएफ अकाउंट्स हैं। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान विदड्रॉल में 33 फीसदी इजाफा हुआ है। इस दौरान 73498 करोड़ रुपये की निकासी की गई जबकि पिछले साल समान अवधि में 55125 करोड़ रुपये विदड्रॉ किए गए थे। लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

पीएफ निकालने के लिए स्पेशल विंडो

कोरोनावायरस महामारी ने कारोबार जगत के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां पैदा की है। कई बिजनस बंद हो गए हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। 2020 में ईपीएफओ से आंशिक निकासी में भी तेजी आई है। 2019 में इसकी संख्या 54.4 लाख थी जो 2020 में दोगुनी होकर 1.3 करोड़ पहुंच गई। सरकार ने कोरोना संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खातों से पैसा निकालने का मौका दिया था। उन्हें अपनी बचत का 75 फीसदी तक विदड्रॉ करने की अनुमति दी थी। कोरोना संकट के दौरान नौकरी गंवाने वाले कई लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था।

फियो ने कंटेनरों की अनुपलब्धता के समाधान के लिए लॉन्च किया 'कंटेनर मांग ई-मॉड्यूल'

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कंटेनरों की आवश्यकता के आकलन के साथ ही उनकी पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए फियो ने पहले स्तर का एक मार्केटप्लेस विकसित किया है, जहाँ पर निर्यातक अपनी कंटेनर मांग को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

इस ई-मॉड्यूल से देश में कंटेनरों की आवश्यकता का जमीनी स्तर पर आकलन करने के साथ ही निर्यातक अपनी जरूरतों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर मोलभाव करने में भी सक्षम होंगे। इससे संबंधित वेब लिंक जारी कर दिया गया है और देश भर के निर्यातकों ने विभिन्न मूल-गंतव्य जोड़ों के लिए अपनी कंटेनर की जरूरत दर्ज करना शुरू कर दिया है। ई-मॉड्यूल से अपलोड की गई कंटेनरों की मांग शिपिंग लाइन्स/ फ्रेट फॉरवर्डर्स/ अन्य को भी दिखने लगी है, जिससे वे इन मांगों को पूरा करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर सकते हैं। इससे उन्हें देश में कंटेनरों की मांग का बेहतर आकलन करने में भी मदद मिलेगी, जिससे कंटेनरों की पोजिशन बदलने या खाली भेजा जा सकेगा।

ई-मॉड्यूल से निर्यातकों द्वारा उठाई गई कंटेनरों की कमी की समस्या का भी समाधान निकलेगा, जिससे उनकी आपूर्ति प्रभावित हो रही है और देश का निर्यात घट रहा है। हालांकि शिपिंग लाइन्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि अफ्रीका के कुछ स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों के लिए 1-3 दिन के बीच कंटेनर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका कहना है कि अफ्रीका में जहाजों की भीड़ और बर्थिंग के चलते इन स्थानों पर 8-10 दिन का समय लग रहा है। व्यापार और उद्योग जगत ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके सामने आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सही समय पर उठाया गया कदम है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।